THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) Certain oil and Gas projects included in the Seventh Plan are being discussed for assistance with the World Bank. However, the final selection of projects will be based on Plan allocations, proposals received and projects accepted by the Bank for funding within the overall figure of commitment indicated annually by the World Bank at the consortium meeting.

मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

2254. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 29 अक्तूबर, 1985 को प्रस्तुत की जाने वाली मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन सिफारिशों को किस प्रकार लागू करने का विचार रखती है और इन्हें किस तारीख से लागू किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैय्या) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 17-7-1985 की अधिसूचना द्वारा दो मजदूरी बोर्ड गठित किए हैं- एक मजदूरी बोर्ड श्रमजीवी पत्रकारों के लिए और दूसरा गैर श्रम जीवी समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए । चीनी उद्योग श्रमिकों के लिए एक गैर सांविधिक मजदूरी बोर्ड भी दिनांक 17-7-1985 की अधिसूचना द्वारा गठित किया गया है । इन मजदूरी बोर्डों ने हाल ही में काम करना शुरू किया है और उन्हें अपनी रिपोर्टों को प्रस्तुत करने मे कुछ समय लगेगा । उनकी सिफारिशों को लागू करने का प्रश्न तभी उठेगा जब वे अपनी रिपोर्टों को अन्तिम रूप दे देगें और उन्हें प्रस्तुत कर देंगे ।

Fraudulent dealing in the State Bank of Patiala

2255. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Vigilance Commission in its Annual Report has referred to a fraudulent dealing in the State Bank of Patiala regarding sanctioning of loans to fictitious borrowers for the purchase of bufalloes; and

(b) if so, what action Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) The Central Vigilance Commission during the course of examination of a fraud case pertaining to the State Bank of Patiala had observed that in a loan function some loans sanctioned for purchase of bufalloes were disbursed to borrowers, who had given wrong names and addresses. The Central Bureau of Investigation registered a case on 14-11-80 and there after filed a chargesheet in a court of law.

स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा गलत भुगतान

2256. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इन्दौर की चांदनी चौक, दिल्ली की शाखा द्वारा 5000 रुपए के दो ड्राफ्टों का भुगतान सही व्यक्ति की बजाय गलत व्यक्ति को कर दिया गया है; और

(ख) इस मामले में बैंक द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विशिष्ट ब्यौरे के बिना माननीय सदस्य जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं वह स्पष्ट नहीं है अलबत्ता, स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि पार्टी का एक मामला है, जिसने पांच-पांच हजार रुपए के दो ड्राफ्टों की रकम न मिलने का दावा किया है । स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उसकी जांच से यह पता चलता है कि

ड्राफ्ट आदाता द्वारा पृष्ठांकित किए गए थे और बैंक द्वारा उनका भुगतान सामान्य समाशोधन के माध्यम से कर दिया गया था। फिर भी, शिकायत प्राप्त होने पर, पंजाब नेशनल बैंक, माडल टाउन शाखा के परामर्श से, जिसके जरिए ये ड्राफ्ट समाशोधन के लिये पृष्ठांकित किए गए थे, मामले की जांच की जा रही है।

बस्तर, मध्य प्रदेश में डोलामाइट परियोजना

2227. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्तर, मध्य प्रदेश में प्रस्तावित डोलोमाइट परियोजना के निर्माण कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने काकरघाटी में डोलोमाइट खनन संबंधी पट्टा देने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) मचकोट डोलोमाइट परियोजना के लिए खनन पट्टा लेना संभव नहीं है क्योंकि डोलोमाइट के निक्षेप आरक्षित वन-क्षेत्र में हैं, जहां बढ़िया किस्म के साल वृक्ष है। इस बात को देखते हुए प्रस्तावित डोलोमाइट परियोजना के निर्माण की प्रगति का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने काकरघाट क्षेत्र में किसी खनन पट्टे के लिए आवेदन नही दिया है।

मैसर्स प्रोग्रेसिव कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के विरुद्ध आरोप

2228. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मैसर्स प्रोग्रसिव कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रीकृत बैंकों से और मध्य प्रदेश सरकार से धोखाधड़ी और अनियमित तरीकों से ऋणों की बड़ी राशि प्राप्त की है ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी पर भारी कर अपवंचन का दोष भी लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी के मामलों की कोई जांच कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार को इस फर्म के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मामले की जांच करवाई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि इस एकक के और इसकी सम्बद्ध कम्पनियों के कुछ बैंकों में जो खाते हैं वे संतोषजनक नहीं है। सम्बद्ध बैंक इस मामले में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक भारी रकमों की करों की चोरी का संबंध है इस समूह से सम्बद्ध सभी मामले एक ही स्थान पर गहराई से और समन्वित रूप से जांच किए जाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इक्ट्ठे कर दिए गए है।

2259. [*Transferred to the 16th December, 1985.*]

Exports of essential commodities

2260. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Will the Minister of COMMERCE be peased to state the quantity and value of exports during the years 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 (upto September; 1985) of superfine, fine, medium and coarse varieties of rice, sugar, steel cement, other food products, fish, meat and other commodities of daily use?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI KHURSHID ALAM KHAN):